किसानों को गेहूं पर प्रति क्विंटल 40 रुपए बोनस

प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी हरी झंडी

भोपाल, 17 मार्च. प्रदेश में किसानों को मौजूदा सीजन में गेहूं उपार्जन पर प्रति क्विंटल 40 रुपए बोनस दिया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस संबंध में पहले ही घोषणा कर दी थी. लिहाजा मंगलवार को इस संबंध में पेश प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है.

यहां बता दें कि केंद्र सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है. पिछले वर्ष के मुकाबले एमएसपी में 160 रुपए की बढ़ोतरी की गई है. वहीं अब इसमें 40 रुपए बोनस के और जुड़ जाएंगे. इससे प्रदेश में अब गेहूं की सरकारी खरीदी पर किसानों को प्रति क्विंटल 2625 रुपए का भुगतान किया जाएगा. प्रदेश में मौजूदा सीजन में गेहूं उपार्जन के लिए 19 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है. पिछले वर्ष राज्य सरकार ने 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया था, लेकिन इस बार इसमें मामूली बढ़ोतरी की है, पिछले वर्ष राज्य सरकार ने 2600 रुपए प्रति क्विंटल में गेहूं की खरीदी की थी. पिछले वर्ष एमएसपी 2425 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई थी. निर्णय अनुसार उपार्जित गेहूं में से भारत सरकार द्वारा स्वीकार न की जाने वाली सरप्लस मात्रा का निस्तारण मप्र स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा खुली निविदा के माध्यम से किया जाकर इस पर होने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा. किसानों को बोनस राशि का भुगतान विभागीय मद में बजट प्रावधान कराकर तथा सरप्लस मात्रा के निस्तारण व्यय की प्रतिपूर्ति मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के तहत आवंटित बजट से किया जाएगा. कैबिनेट ने शासकीय आवास गृह, विश्राम गृहों के रखरखाव और अनुरक्षण के लिये एक अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की निरंतरता के लिए के लिए 200 करोड़ 35 रूपये की स्वीकृति दी है.

उज्जैन में दो ऐलिवेटेड कॉरिडोर बनेंगे

कैबिनेट ने उज्जैन में दो ऐलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसी के साथ लोक निर्माण विभाग के दूसरे विकास कार्यों को भी हरी झंडी दी गई है, जिस पर कुल 4525 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी. निर्णय के तहत उज्जैन शहर में चिमनगंज मंडी इंद्रा नगर चौराहा से इंदौर गेट तक 4-लेन ऐलिवेटेड कॉरिडोर एवं निकास चौराहा से इंदौर गेट तक 2 लेन ऐलिवेटेड कॉरिडोर लंबाई 5 .32 कि .मी . के निर्माण कार्य को विभागीय सूचकांक से मुक्त रखते हुए लागल राशि 945 करोड़ 20 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई . मप्र रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028 और जन भागीदारी अंतर्गत विकास हेतु अनुदान योजना की एक अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की निरंतरता के लिए 7 करोड़ 38 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है . एनडीबी से वित्त पोषण पुल और सड़क निर्माण की योजना की निरंतरता के लिए 50 करोड़ 10 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है . इसी तरह मप्र रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम-6 की 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की निरंतरता के लिए 1543 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है .

प्रदेश के कई जिलों में 3 दिन बारिश का अलर्ट

18 से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ

भोपाल, 17 मार्च. मध्यप्रदेश में लगातार बढ़ती गर्मी के बीच अब मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार 18 मार्च से एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिलेगा.

इसके चलते 18 से 20 मार्च तक आंधी, बारिश और गरज-चमक का दौर बना रह सकता है. राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर सहित कई प्रमुख शहरों में मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं. हालांकि इससे पहले मंगलवार तक तेज गर्मी और धूप लोगों को परेशान करती रहेगी.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन के अनुसार यह सिस्टम 17 मार्च की रात से सक्रिय होना शुरू होगा और अगले तीन दिनों तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों को प्रभावित करेगा. कहीं तेज हवाएं चलेंगी, तो कहीं हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है.

फिलहाल प्रदेश में गर्मी का असर बना हुआ है. कई जिलों में तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है. खरगोन में सबसे अधिक 38.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.

इसके अलावा नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, रायसेन, सिवनी, मंडला, टीकमगढ़, सागर और खजुराहो में भी पारा 37 डिग्री के ऊपर रहा. बड़े शहरों में जबलपुर सबसे गर्म रहा, जहां 35 .8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. भोपाल में 35 .2 डिग्री, इंदौर और उज्जैन में 35 डिग्री, जबकि ग्वालियर में 34 .1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. मौसम विभाग ने आगे चेतावनी दी है कि अप्रैल और मई में प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ सकती है. अनुमान है कि इस दौरान 15 से 20 दिनों तक लू चल सकती है. मार्च के अंतिम सप्ताह से ही इसका असर दिखने लगेगा.

एक नजर में

नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवी समागम का समापन आज

भोपाल. 'मध्यप्रदेश नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवी समागम 2026' का समापन आज 18 मार्च को जहांगीराबाद स्थित होमगार्ड्स परेड ग्राउंड में किया जाएगा. कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. इस समागम का आयोजन नागरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने तथा आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवकों की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया है. समापन समारोह के दौरान नागरिक सुरक्षा गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें प्रदेश में तैयारियों और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को सुदृढ़ करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला जाएगा.

एक अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीदी

भोपाल. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी इंदौर, उज्जैन, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग में एक अप्रैल से तथा शेष संभागों में 7 अप्रैल से की जाएगी. गेहूं की खरीदी शासकीय कार्य दिवसों में सुबह 8 से रात 8 बजे तक की जाएगी. उन्होंने बताया है कि सरकार ने गेहूं खरीदी पर 40 रुपये अतिरिक्त बोनस देने का भी फैसला लिया है. अब प्रदेश में गेहूं की खरीदी 2625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी. मंत्री राजपूत ने बताया है कि रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिये कुल 19 लाख 4 हजार 651 किसानों ने पंजीयन कराया है.

बड़ा बैंक फ्रॉड : फर्जी कागज, गलत वैल्यूएशन पर 33 लाख का लोन

- घोटाले में शामिल बैंक अफसरों समेत 7 पर केस दर्ज
- ईओडब्ल्यू ने फर्जी कागजों से लोन लेने वाले गिरोह को किया बेनकाब
- एक ही संपत्ति को दो बैंकों में गिरवी रखकर की धोखाधड़ी

नव भारत न्यूज

इंदौर. फर्जी दस्तावेजों और गलत वैल्यूएशन के जरिए 33 लाख रुपए का बैंक लोन लेने का बड़ा घोटाला सामने आया है. एक ही संपत्ति को दो अलग-अलग बैंकों में गिरवी रखकर किए गए इस फर्जीवाड़े का खुलासा एनपीए घोषित होने के बाद हुआ. मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने जांच कर बैंक अधिकारियों सहित 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरोह का पर्दाफाश किया है.

संपत्ति के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर केनरा बैंक से 33 लाख रुपए का लोन हासिल करने के मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने बड़ा खुलासा करते हुए बैंक अधिकारियों सहित 7 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. जांच में सामने आया कि पहले से ही दूसरे बैंक में गिरवी रखी संपत्ति को दोबारा कूटरचित दस्तावेजों के जरिए बंधक बनाकर यह धोखाधड़ी की गई. ईओडब्ल्यू को केनरा बैंक के डिप्टी जनरल मैनेजर आनंद टोटड द्वारा शिकायत की गई थी, जिसमें बताया गया कि मेसर्स अबु रोड लाइन्स के संचालक करामत खान और अन्य ने वर्ष 2017 में सिंडीकेट बैंक (वर्तमान केनरा बैंक) नंदा नगर शाखा से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 33 लाख रुपए का ऋण लिया था.

ईओडब्ल्यू जांच में बैंक अधिकारियों द्वारा की गई केवायसी और ड्यू डिलिजेंस प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं. पैनल एडवोकेट और मूल्यांकनकर्ता द्वारा भी गलत रिपोर्ट देकर लोन स्वीकृति में अहम भूमिका निभाई गई. प्रकरण में करामत खान (प्रोपराइटर मेसर्स अबु रोड लाइन्स), मोहम्मद रफीक, तत्कालीन ब्रांच मैनेजर जतिन गुप्ता, क्रेडिट मैनेजर कमलेश दरवानी, संपत्ति मूल्यांकनकर्ता इंजीनियर सुनील जैन सहित जावेद खान और मोहम्मद इरफान खान के खिलाफ केस दर्ज किया है. ईओडब्ल्यू ने आरोपियों पर भादंवि की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है. मामले में जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी.

ऐसे रचा गया पूरा फर्जीवाड़ा...

जांच में सामने आया कि आरोपी ने वर्ष 2016 में बैंक में खाता खोलकर पहले 10 लाख रुपए का लोन लिया था. बाद में ऋण सीमा बढ़ाने के लिए ग्रीन पार्क कॉलोनी स्थित मकान नंबर 435-ए के फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए. इस पर पैनल एडवोकेट और मूल्यांकनकर्ता की भ्रामक रिपोर्ट के आधार पर 21 नवंबर 2017 को 33 लाख रुपए का लोन स्वीकृत कर दिया.

पहले से गिरवी थी संपत्ति, फिर भी मिल गया लोन-जब लोन की अदायगी नहीं हुई, तो 30 दिसंबर 2019 को खाते को एनपीए घोषित कर दिया. सरफेसी कार्रवाई के दौरान खुलासा हुआ कि संबंधित संपत्ति पहले से ही इंडियन बैंक में गिरवी थी और वर्ष 2021 में उसकी नीलामी भी हो चुकी थी.

अब 90% उपभोक्ता करा रहे ऑनलाइन बुकिंग

ऑइल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बैठक में दी जानकारी

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 17 मार्च. पश्चिम एशिया में चल रहे घटनाक्रम के मद्देनजर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल, पीएनजी, सीएनजी तथा घरेलू गैस की आपूर्ति की लगातार समीक्षा का दौर जारी है.

मंगलवार को अपर मुख्य सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण रश्मि अरूण शमी ने मंत्रालय में खाद्य विभाग के अधिकारियों तथा ऑइल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ स्थिति की समीक्षा की. इस दौरान ऑइल कंपनियो के प्रतिनिधि ने

बताया कि पूर्व में जहां 84 फीसदी उपभोक्ता ऑनलाइन बुकिंग करवा रहे थे वह संख्या बढकर 90 फीसदी हो गयी है. कंपनियों ने मोबाइल ऐप, एसएमएस, व्हाट्सएप तथा आईवीआरएस कॉल द्वारा गैस बुकिंग की सुविधा प्रदान की है. उन्होंने कहा कि उपभोक्ता बुकिंग के लिए इन डिजिटल माध्यम का प्रयोग करें तथा अनावश्यक रूप से एजेंसी पर जाने से बचे. बैठक में बताया गया कि घरेलू एलपीजी के उत्पादन में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा निरंतर आपूर्ति जारी है. शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों को आवश्यकता की 100 प्रतिशत गैस की आपूर्ति की जा रही है. केंद्र सरकार द्वारा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए विशेष छूट के निर्देश भी जारी किये है.

बैठक में गैस एजेंसियों के संचालन, सिलेंडर वितरण की समयबद्धता और उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों की स्थिति की भी समीक्षा की जा रही है.

1341 स्थानों पर कार्रवाई, 1827 सिलेंडर जब्त

एलपीजी की कालाबाजारी तथा जमाखोरी के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है. प्रदेश में 1341 स्थानों पर कार्यवाही कर 1827 सिलेंडर जब्त किये गए. पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी तथा घरेलू एलपीजी गैस की उपलब्धता के सम्बन्ध में ऑयल कंपनियों से समन्वय के लिए राज्य स्तर पर 6 सदस्यीय समिति भी गठित की गयी है, जो प्रदेश में कामर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर की सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए निरंतर निगरानी करेगी.

एचपीवी टीकाकरण में बड़ी सफलता

1 लाख से अधिक बालिकाएं सुरक्षित

14 वर्ष की किशोरियों का टीकाकरण पूर्ण

15 दिन में एक लाख बेटियों को लगाया एचपीवी वैक्सीन

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 17 मार्च. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एचपीवी टीकाकरण अभियान में मात्र 15 दिनों में प्रदेश की एक लाख से अधिक बेटियों को वैक्सीन लगाकर मप्र के देश में प्रथम रहने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम, एएनएम, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में बेटियों को सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध सुरक्षा का सशक्त कवच प्रदान करने के लिए प्रारंभ अभियान के प्रदेश में सफल क्रियान्वयन में इस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है.

प्रदेश में मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, राजगढ़ और खरगोन जिलों का विशेष योगदान रहा. अभियान के सफल संचालन के लिए जिला स्तर पर कलेक्टरों के नेतृत्व में विभिन्न विभागों और संगठनों का समन्वय किया गया.

मध्यप्रदेश में एचपीवी टीकाकरण अभियान के तहत 14 वर्ष आयु वर्ग की एक लाख से अधिक किशोरी बालिकाओं का सफल टीकाकरण पूरा कर लिया गया है. यह उपलब्धि प्रदेश को देश में इस अभियान में अग्रणी बनाती है. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने इस सफलता पर स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और सहयोगी संस्थाओं को बधाई दी. उन्होंने कहा कि यह पहल बेटियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने बताया कि इस अभियान का राष्ट्रीय शुभारंभ नरेन्द्र मोदी ने 28 फरवरी 2026 को अजमेर से किया था.

अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान

43 हथियार कई जिलों से जब्त

विशेष संवाददाता

भोपाल, 17 मार्च. मध्यप्रदेश पुलिस ने अपराधों पर नियंत्रण और अवैध हथियारों के व्यापार व उपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से सख्त कार्रवाई करते हुए पिछले दो सप्ताह में प्रदेश के विभिन्न जिलों से कुल 42 अवैध हथियार जब्त किए हैं.

इंदौर में पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से अवैध हथियारों की आपूर्ति करने वाले एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से छह देशी पिस्टल बरामद कीं. एक अन्य आरोपी को भी अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया, जिससे जिले में

कुल जब्ती संख्या सात हो गई. दतिया में विभिन्न थाना क्षेत्रों की संयुक्त कार्रवाई में 11 अवैध हथियार बरामद किए गए, जहां लूट और फायरिंग जैसी घटनाओं में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

मुरैना में छह, ग्वालियर में चार तथा जबलपुर में तीन अवैध हथियार जब्त किए गए. ग्वालियर में हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामलों में फरार आरोपियों को भी पकड़ा गया.

शिवपुरी, छतरपुर और पन्ना में दो-दो तथा सागर, विदिशा, खरगोन, सतना और निवाड़ी जिलों में एक-एक अवैध हथियार जब्त किया गया. पुलिस ने कहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी पर बल

भोपाल में भाजपा कोर कमेटी बैठक संपन्न

भोपाल, 17 मार्च. राजधानी भोपाल में प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की अध्यक्षता में भिंड जिले की भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई. बैठक में संगठनात्मक विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हुए आगामी कार्यक्रमों और गतिविधियों की रूपरेखा तय की गई.

बैठक के दौरान उपस्थित पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने अपने सुझाव साझा किए. इन पर सकारात्मक विचार-विमर्श करते हुए संगठन को और अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाने पर सहमति बनी. साथ ही संगठन की गतिविधियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया.

कार्यकर्ताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए सभी से सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया. संगठनात्मक समन्वय मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने पर भी विशेष बल दिया गया. बैठक में कैबिनेट मंत्री एवं मेहगांव विधायक राकेश शुक्ला, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, संभाग प्रभारी डॉ. अभय यादव, जिला प्रभारी हमीर सिंह पटेल, जिलाध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया, विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे.

बैतूल में सुरभि खण्डेलवाल की श्रद्धांजलि सभा आज

भोपाल, 17 मार्च. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल की सुपुत्री सुश्री सुरभि खण्डेलवाल के देवलोकगमन पर पुण्य आत्मा की पावन स्मृति में 18 मार्च बुधवार को बैतूल में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी.

प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल ने आज बताया कि श्रद्धांजलि सभा बुधवार को दोपहर 2 बजे से विजय सेवा न्यास के सामने न्यू बैतूल ग्राउंड, कोठी बाजार में आयोजित की जाएगी. श्रद्धांजलि सभा में पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक बंधु,

पार्टी कार्यकर्ता, गणमान्य नागरिक एवं परिजन स्वर्गीय सुश्री सुरभि खंडेलवाल को श्रद्धासुमन अर्पित कर शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करेंगे.

पत्रकार वार्ता | अब मध्यप्रदेश राज्य के रूप में प्रदेश इकाई बनेगी, सात संभाग होंगे

आरएसएस की भौगोलिक संरचना का पुनर्गठन

भोपाल, 17 मार्च. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने भौगोलिक क्षेत्र का पुनर्गठन किया है. इसी क्रम में संघ के तीन प्रांत मध्य भारत, मालवा और महाकौशल अब मध्यप्रदेश राज्य के रूप में जाने जाएंगे. यह व्यवस्था मार्च 2027 से लागू हो जाएगी.

मध्य भारत प्रांत के संघचालक अशोक पांडेय ने मंगलवार को विश्व संवाद केंद्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी. श्री पांडेय ने हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की हरियाणा के

पट्टीकल्याणा (समालखा) में संपन्न बैठक में हुए प्रमुख निर्णयों की जानकारी दी.

श्री पांडेय ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अब मध्य भारत प्रांत, मालवा प्रांत और महाकौशल प्रांत के स्थान पर एक ही इकाई मध्यप्रदेश राज्य गठित करने का निर्णय हुआ है. मध्यप्रदेश प्रांत में सात संभाग समाहित किए गए हैं. इनमें ग्वालियर और भोपाल के अलावा उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, रीवा और सागर संभाग शामिल हैं. नयी व्यवस्था मार्च 2027 से प्रभावी होगी. उन्होंने बताया कि इसी तरह के बदलाव राष्ट्रीय स्तर पर भी हुए हैं.

सम्मेलनों में 52 लाख नागरिकों ने की सहभागिता

श्री पांडेय ने बताया कि संघ के शताब्दी वर्ष के निमित्त अनेक कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय हुआ है. वर्तमान में मध्य भारत प्रांत में संघ की रचना से महानगरीय और ग्रामीण जिलों के 2481 स्थानों पर 3842 शाखाएं चल रही हैं. इसके साथ ही 689 स्थानों पर 736 साप्ताहिक मिलन के रूप में संघकार्य चल रहे हैं. संघ की स्थापना के एक सौ वर्ष पूर्ण होने पर विजयादशमी उत्सव, व्यापक गृह संपर्क अभियान, हिंदू सम्मेलन और प्रमुखजन गोष्ठी का आयोजन भी हो चुका है. उन्होंने बताया कि भोपाल में सरसंघसंचालक डॉ मोहन भागवत का भी प्रवास हुआ और प्रमुखजन गोष्ठी, युवा संवाद, सामाजिक सद्भाव बैठक और स्त्री शक्ति संवाद का आयोजन किया गया. 80 हजार स्वयंसेवकों ने 27 लाख से अधिक परिवारों से संपर्क किया है. हिंदू सम्मेलनों में 52 लाख से अधिक नागकिरों ने सहभागिता की है.

रीवा में राष्ट्रीय संगोष्ठी आज

रीवा. शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, रीवा के भूविज्ञान विभाग द्वारा 18 और 19 मार्च को 'प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरणीय स्थिरता' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जा रही है. इस संगोष्ठी में देशभर के विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और शोधार्थी भाग लेंगे. कार्यक्रम का उद्घाटन 18 मार्च को स्वामी विवेकानंद सभागार में होगा, जिसमें प्रो. कृष्ण बिहारी पांडेय मुख्य अतिथि रहेंगे. संगोष्ठी में जलवायु परिवर्तन, खनिज प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी. प्राचार्य प्रो. (डॉ.) रवीन्द्र नाथ तिवारी ने बताया कि यह आयोजन छात्रों और शोधार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा.

पेज एक का शेष

हर श्रद्धालु हमारा अतिथि होगा : सीएम

ऐसे में सरकार का प्रयास है कि उज्जैन को आधुनिक सुविधाओं से युक्त, स्वच्छ और व्यवस्थित आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित किया जाए, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो. सिंहस्थ को भव्य और व्यवस्थित बनाने के लिए राज्य सरकार ने 13 हजार 851 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को स्वीकृति दी है. वर्ष 2026-27 के बजट में सिंहस्थ की तैयारियों के लिए 3 हजार 60 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान रखा गया है. कार्यक्रम में 77 करोड़ 14 लाख रुपये की लागत से बनने वाले भव्य गीता भवन की आधारशिला रखी गई. इसके साथ ही 30 करोड़ 68 लाख रुपये की लागत से विक्रम नगर रेलवे ओवर ब्रिज का भूमिपूजन भी किया गया. प्रधानमंत्री का मिल रहा सहयोग : सीएम बोले केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने एन एच 752 डी के बदनावर-पेटलावद-थांदला खंड को फोर लेन बनाने की स्वीकृति दी है, जिससे उज्जैन का संपर्क दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से और मजबूत होगा तथा क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी. शहर और आसपास के क्षेत्रों में 11 नई सड़कों के निर्माण का कार्य भी शुरू किया गया है, जिससे यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और सिंहस्थ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी. 64 कला 14 विद्या श्री कृष्ण ने यहीं सीखी : मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन केवल धार्मिक नगरी ही नहीं बल्कि शिक्षा, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का भी केंद्र रहा है.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60